2 ब्रह्मपुत्र को धुबरी से सैदिया तक (891 कि० मी०) ।

3 पश्चिम तटीय नहर को कोट्टापुरम से कोलम तक (168 कि०मी०) और उद्योग मंडल नहर (23 कि०मी०) तथा चम्पाकारा नहर (14 कि०मी०) टर्मिनलों, नौचालन उपकरणों, आदि जैसी मूलभूत संरचनात्मक सुविधाओं के साथ-साथ उक्त राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास और रख-रखाव के लिए भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की योजनायें चल रही हैं। गोदावरी नदी के चेरला-राजमुंदरी खंड को राष्ट्रीय जलमार्ग सं०-4 के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव पर कार्यवाही की जा रही है। गोवा में मंडोवी, जुआरी नदियों और कम्बरजुआ नहर को राष्ट्रीय जलमार्ग के रूप में घोषित करने के संबंध में, आगे कार्यवाही करने से पहले, गोवा सरकार से अपनी सहमति भेजने का अनुरोध किया गया है ।

(घ) से (च) उपर्युक्त राष्ट्रीय जल-मार्गों को पूर्णतः प्रचालनात्मक बनाने के बाद ही देश की अनेक बड़ी और छोटी नदियों को आपस में जोड़कर जलमार्गों के विस्तार के प्रश्न पर विचार किया जाएगा ।

सड़क परियोजनाओं के निर्माण में विलम्ब

1324 **श्री राम जेठमलानी** : क्या जल-भूतल परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान 10 मार्च, 1994 के "दि टाइम्स आफ इंडिया" में "पैनल टू डिस्कस रोड प्रोजेक्ट्स डिले" शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा गठित की गई सचिव स्तरीय समिति ने कुल 20 करोड़ अथवा उससे अधिक की लागत वाली पुल अथवा सड़क निर्माण परियोजनाओं में हुए विलम्ब पर विचार किया है;

(ग) यदि हां, तो उन परियोजनाओं के नाम क्या हैं तथा उनके निर्माण में कितना-कितना विलम्ब हो चुका है एवं उनकी निर्माण लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है और यह वृद्धि मूल लागत का कितना-कितना प्रतिशत है ;

(घ) क्या उक्त समिति ने परि-योजनाओं के निर्माण के संबंध में अपनी सिफारिशें सरकार को सौंप दी हैं; और

(ङ) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा अब तक उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जगदीश टाईटलर) : (क) और (ख) जी, हां ।

(ग) विवरण में दिए हैं । (नीचे देखिये) ।

(घ) और (ङ) जी, हां । समिति ने मोटे तौर पर एक अलग संगठन की स्थापना करने, राज्य सरकारों द्वारा चालू कार्यों की आवधिक समीक्षा करने, परि-योजना का संपूर्ण समन्वय और कड़ा पर्यवेक्षण करने, कार्यान्वयन और कड़ी निगरानी तथा जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में शीर्ष प्रबन्ध समिति द्वारा कठिनाईयों का समाधान करने की सिफारिश की है। समिति की सिफारिशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

विवरण

सड़क परियोजनाओं के नाम उनके निर्माण में विलम्ब की अवधि तथा उनकी निर्मित लागत

क्र० सं०	परियोजना का नाम	लागत			टिप्पणियां
		अनुमोदित मूल (संशोधित) (करोड़ रु०)	पूर्वानुमानित	मूल (संशोधित) पर प्रतिशत वृद्धि	
1	2	3	4	5	6
1	वाराणसी बाईपास और गंगा नदी पर बड़ा पुल (रा०रा० 2) उ०प्र०	41.60 (49.92)	70.42	69 (41)	
2	दिल्ली मथुरा राजमार्ग पर चार लेन बनाना (रा०रा० 2) उ०प्र०	91.94 (114.24)	132.91	44 (16)	
3	अहमदाबाद-बड़ोदरा एक्स-प्रैसवे (गुजरात)	128.40 (137.20)	279.94	118 (104)	
4	मुरथल-करनाल सड़क (रा०रा० 1) पर चार लेन बनाना (हरि०)	42.50 (40.16)	53.54	25 (33)	
5	दुर्गापुर एक्सप्रैसवे (प० बंगाल)	48.60 (54.17)	112.06	130 (107)	
6	दिल्ली जयपुर खंड पर चार लेन बनाना (रा०रा० 8)	93.66	93.66	—	
7.	इन्दौर-देवास खंड पर चार लेन बनाना (रा०रा० 3) मा० प्र०	29.53	29.53	—	शुरू नहीं किया गया। निविदा कागजातों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।
8	इंदौर बाईपास का निर्माण (रा०रा० 3) म० प्र०	73.44	73.44	—	—वही—
9	कटक-जगतपुर खंड पर चार लेन बनाना (रा०रा० 5) उड़ीसा	133.38	133.38	—	जल-भूतल परिवहन मंत्रालय में निविदायें प्राप्त हो गई हैं और उनपर कार्रवाही की जा रही है।

विलम्ब के कारण :

इन परियोजनाओं के विलम्ब के लिए मुख्य कारण ठेका संबंधी समस्यायें हैं जैसे ठेकेदारों द्वारा मुकदमेबाजी, ठेकेदारों द्वारा अनुसूची के अनुसार परियोजनाओं को क्रियान्वित न करना ठेकेदारों द्वारा दरों के संशोधन की मांग और ठेकेदारों को बदलना आदि। ठेकेदारों द्वारा अपर्याप्त संयंत्र और उपकरण लगाना और ठेका देने में विलम्ब भी देरी के कुछ अन्य कारण हैं।